लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 208

18 जुलाई, 2016 को उत्तर के लिए

इस्पात क्षेत्र हेतु निधि

208. श्री के अशोक कुमार:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार घरेलू इस्पात कंपनियों की पूंजीगत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु देश के प्रथम सॉवरिन वैल्थ फंड-राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि (एनआईआईएफ) के अन्तर्गत एक निधि की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पूंजीगत लागत एक प्रमुख कारक है जिससे भारतीय इस्पात उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित होती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह)**

(क): जी नहीं।

(ख): प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) : जी हॉ। भारत में इस्पात परियोजनाओं की पूंजीगत लागत वर्तमान में अन्य देशों की तुलना में अधिक है। इस्पात निर्माता देशों में पूंजी की तुलनात्मक औसत लागत नीचे तालिका में दी गई है:

देश	2015
चीन	5.6 %
जापान	1.2 %
कोरिया	3.7 %
भारत	**12.0** %

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) द्वारा निर्धारित नीतिगत दर के आधार पर ब्याज लागतो के बैंचमार्क तय किये जाते है। सरकार ने निधियों को आकर्षित करने के लिए इस्पात क्षेत्र में 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी है। आरबीआई ने अवसरंचनागत और प्रमुख उद्योगों के लिए दीर्घकालीन परियोजना ऋण हेतु वर्तमान 10-12 वर्षों की अवधि को बढ़ाकर 25 वर्ष तक की अवधि का लोचदार ढॉचा भी लागू किया है।

***